भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,
लांगवुड, शिमला–171001
वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE , SHIMLA
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O COMPLEX
LONGWOOD, SHIMLA-171001
PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL OFFICE, 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / एच.पी. / 01 / 147 / 2019 / एफ.सी. /101 दिनांक: 22 / 06 / 2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय: **Diversion of 8.0678 ha of forest land in favour of M/s Friends Him Energies, C/o Near Happy Sr. Sec. School, Jail Road, Gurdaspur- 143521 for the construction of Siul-iv-SHEP, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P.(Online Proposal No. FP/HP/HYD/35437/2018)**

सन्दर्भ:नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन सरंक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश का पत्रांक–एफ0टी0 48–3785 / 2018 (एफ0सी0ए0), दिनांक 11.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली भेजा गया था, जहां प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत निम्न बिंदुओं पर राज्य सरकार से विशिष्ट टिप्पणी अपेक्षित पाई गई है:–

1. With regards choosing RoW of 15.47 mtr rather 15.0 mtr, the state govt. has cited the practice of use local units (Karma). In modern times, when system of SI units, which have evolved through last century, inability to follow the same by the State does not seem to be acceptable and convincing.
2. The concern of the state to provide for mitigating measures of individual projects in the EMP does not seem to be tenable as it is devoid factual basis. The hydel projects up to 25 MW does not covered under the EIA notifications and hence may not involve preparation of EMPs and also cannot be appraised by the SEAC as adverted by the state. The State Govt. may provide their comments in this regard.

अतः राज्य सरकार उक्त बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगतकरना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीया,

22/06/21

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

for cds record folder